



## ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

---

 [drishtiias.com/hindi/printpdf/graded-response-action-plan](https://drishtiias.com/hindi/printpdf/graded-response-action-plan)

### पिरलिम्स के लिये:

वायु गुणवत्ता सूचकांक, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण

### मेन्स के लिये:

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की विभिन्न श्रेणियाँ

### चर्चा में क्यों?

---

हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया है कि **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)** की "बहुत खराब" एवं "गंभीर" श्रेणी के तहत शामिल उपाय 48 घंटे के दौरान वायु की गुणवत्ता और भी दूषित व निर्धारित स्तर से अधिक होने पर लागू होंगे।

### परमुख बिंदु

---

## ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP):

### ○ परिचय:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता के संबंध में **एमसी मेहता बनाम भारत संघ (2016)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, विभिन्न **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)** के तहत कार्यान्वयन के लिये एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इन्हें मुख्य श्रेणियों में अर्थात् **औसत से खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।**

इसमें **"गंभीर + या आपातकाल"** की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है।

- इस योजना को **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में अधिसूचित** किया गया था।
- इसने वायु की गुणवत्ता खराब होने पर किये जाने वाले उपायों को **संस्थागत रूप** दिया।
  - यह योजना **प्रकृति में वृद्धिशील** है, इसलिये जब वायु गुणवत्ता 'खराब' से 'बहुत खराब' की ओर बढ़ती है, तो दोनों वर्गों के तहत सूचीबद्ध उपायों का पालन किया जाना चाहिये।
  - यह PM10 और PM2.5 स्तरों को 'मध्यम' राष्ट्रीय AQI श्रेणी से आगे जाने से रोकता है।

### ○ कार्यान्वयन:

- वर्ष 2020 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त **पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA)** राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था।
- EPCA को भंग कर **वर्ष 2020 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था।

CAQM अंतर्निहित उपचारात्मक दृष्टिकोण के साथ **दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध प्रयासों के समन्वय और निगरानी के लिये एक **वैधानिक तंत्र** है।

श्रेणी	परिवेशी कण पदार्थ (PM)	मानक
औसत से खराब	<ul style="list-style-type: none"><li>• PM2.5, 61-120 µg/घन मीटर</li><li>• PM10, 101-350µg/घन मीटर</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करना।</li><li>• सड़कों पर मशीन द्वारा सफाई।</li><li>• पटाखों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करना।</li><li>• कचरा जलाने पर प्रतिबंध।</li></ul>
बहुत खराब	<ul style="list-style-type: none"><li>• PM2.5, 121-250 µg/घन मीटर</li><li>• PM10, 351-430 µg/घन मीटर</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• डीज़ल जनरेटर सेट का उपयोग बंद करना।</li><li>• बस और मेट्रो सेवाओं में वृद्धि एवं मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि।</li><li>• होटल और खुले में स्थित भोजनालयों में कोयले/जलाऊ लकड़ी का उपयोग बंद करना।</li></ul>

गंभीर	<ul style="list-style-type: none"> <li>PM 2.5, 250 µg/घन मीटर से अधिक</li> <li>PM10, 430µg/घन मीटर से अधिक ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सड़क की लगातार मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव करना ।</li> <li>ईट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर को बंद करना ।</li> <li>बदरपुर पावर प्लांट बंद करना ।</li> <li>अलग-अलग दरों वाले सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना ।</li> </ul>
गंभीर+ या आपातकाल	<ul style="list-style-type: none"> <li>PM2.5 ,300 µg/घन मीटर से अधिक</li> <li>PM10, 500µg/घन मीटर से अधिक</li> </ul> <p data-bbox="358 621 711 688">( 48 घंटे या उससे अधिक समय तक स्थिर स्थिति)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) ।</li> <li>निर्माण कार्य बंद ।</li> <li>निजी वाहनों के लिये विषम/सम योजना का प्रारंभ ।</li> <li>स्कूलों को बंद करना ।</li> </ul>

**अन्य उपाय:**

- पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC): 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर में 2000cc एवं उससे अधिक के डीज़ल कारों की बिक्री पर 1% का EPC लगाया ।
- पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क (ECC): वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर ईसीसी लगाया ।

**स्रोत: द हिंदू**